



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2009/फाल्गुन 28, 1930

No. 159]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2009/PHALGUNA 28, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2009

सा.का.नि. 178(अ).—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है :—

यतः, मुझे, भारत की राष्ट्रपति, प्रतिभा देवीसिंह पाटील को मंचालय राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा मुझे प्राप्त उक्त रिपोर्ट और अन्य सूचना पर गौर करने के पश्चात्, मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उक्त राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः, अब, मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उद्घोषणा करती हूँ कि मैं —

- (क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उक्त राज्य के राज्यपाल में निहित या उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालती हूँ ;
- (ख) घोषित करती हूँ कि उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और
- (ग) निम्नलिखित आनुवंशिक और पारिणामिक उपबंध करती हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—
 - (i) इस उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए यथा पूर्वोक्त कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;
 - (ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलंबित किया जाता है; अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा उक्त राज्य के विधानमंडल को निर्देश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों को, उक्त राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की सरकार के कार्यों को मंत्रियों के बीच बांटने से है;

अनुच्छेद 167;

अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा किसी संकल्प के पारित किए जाने से है;

अनुच्छेद 174 का खण्ड (1) और खण्ड (2) का उप-खण्ड (क);

अनुच्छेद 175 से 178 (जिसमें ये दोनों शामिल हैं);

अनुच्छेद 179 के खण्ड (ख) एवं (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक;

अनुच्छेद 180, 181, 188, 189, 193, 194, 196, 198 और अनुच्छेद 199 का खण्ड (3) और (4);

अनुच्छेद 208 से 211 (जिसमें ये दोनों शामिल हैं);

अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का संबंध उक्त राज्य के विधानमंडल के समक्ष ज्ञापन सहित रिपोर्ट रखे जाने से है;

- (iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, उस राज्य के संबंध में, राष्ट्रपति के प्रति निर्देश समझा जायेगा, और उसमें उक्त राज्य के विधानमंडल के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और शक्तियों से है, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निर्देश समझा जाएगा, और, विशिष्टतया, अनुच्छेद 213 में उक्त राज्य के राज्यपाल और विधानमंडल के प्रति निर्देशों का अर्थ

क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निर्देश समझा जाएगा:

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 159 (जिसमें ये दोनों शामिल हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से पैरा 4 (जिसमें ये दोनों शामिल हैं) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राष्ट्रपति को इस खण्ड के उप-खण्ड (i) के अधीन, उस सीमा तक जहां तक वह उचित समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित नहीं करेगी;

- (iv) संविधान में उक्त राज्य के विधानमंडल के, या उसके द्वारा बनाए गए, अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसा अर्थ लगाना जाएगा मानों उसके अंतर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा, या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारियों द्वारा उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और मेघालय व्याख्यात्मक तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1972 (1972 का मेघालय अधिनियम, 7), जैसाकि वह मेघालय राज्य में लागू है और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग, जितना राज्य की विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानों यह उक्त राज्य के विधानमंडल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली

दिनांक : 19 मार्च, 2009

(प्रतिभा देवीसिंह पाटील)

राष्ट्रपति

[फा. सं.-V-11013 1/2009-सी.एस.आर.]

मधुकर गुप्ता, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2009

G.S.R. 178(E).— The following Proclamation by the President is published for general information:-

WHEREAS, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, have received a report from the Governor of the State of Meghalaya and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as the "Constitution");

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I –

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:-
 - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:-

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying, before the Legislature of the State, of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;

articles 180, 181, 188, 189, 193, 194, 196, 198 and clauses (3) and (4) of article 199;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii)

any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State

shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State, shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as she thinks fit through the Governor of the said State;

- (iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Meghalaya Interpretation and General Clauses Act, 1972 (Meghalaya Act 7 of 1972), as in force in the State of Meghalaya, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

New Delhi,

The 19th March, 2009

(PRATIBHA DEVISINGH PATIL)
President

[F. No. V/11013/1/2009-CSR]

MADHUKAR GUPTA, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2009

सा.का.नि. 179(अ).—राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन आज मार्च, 2009 के उन्नीसवें दिन अपने द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के अनुसरण में, एतद्वारा, निदेश देती हूँ कि मेघालय राज्य की सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जो उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा स्वयं संभाल ली गई हैं, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली

दिनांक : 19 मार्च, 2009

(प्रतिभा देवीसिंह पाटील)

राष्ट्रपति

[फा. सं.-V/11013/1/2009-सी.एस.आर.]

मधुकर गुप्ता, गृह सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th March, 2009

G.S.R. 179(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this, the 19th day of March, 2009, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Meghalaya and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi,

The 19th March, 2009

(PRATIBHA DEVISINGHI PATHI)

President

[F. No. V/11013/1/2009-CSR]

MADHUKAR GUPTA, Home Secy.